धधकती सुलगती आग नेपाल में

माओवादियों के बंद ने एक बार फिर दहलाया हिमालयी राष्ट्र

पड़ोस

प्रभात कुमार रॉय

समूचे भारत के लिए यह चिंताजनक विषय है कि नेपाल इन दिनों फिर से सुलगने और धधकने लगा है। नेपाल भारत के लिए महज़ एक पड़ोसी देश ही नहीं है वरन सदियों से एक कनिष्ठ भ्रातृभाव वाला राष्ट्र रहा है । इन दिनों नेपाल की हुकूमत का नेतृत्व साम्यवादी नेता माधव कुमार नेपाल के हाथों में है। जो कि अनेक दलों की एक मिली जुली सरकार है जिसमें नेपाली कांग्रेस भी एक घटक दल है। सर्वविदित है कि 601 सदस्यों वाली संविधान सभा के लिए आयोजित हुए आम चुनाव में पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के नेतृत्व में माओवादी नेपाल के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरे थे। एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी दल के साथ मिलकर माओवादी प्रचंड ने प्रधानमंत्री का ओहदा संभाल लिया था। उस वक़्त तो यह उम्मीद बंध गई थी कि शायद अब नेपाल अमन ओ चैन की सांस ले सकेगा। एक दशक तक जारी गृहयुद्ध ने नेपाल को ध्वस्त करके रख दिया था। आखिरकार सामंतशाही का मुकम्मल खात्मा हुआ और बहुदलीय लोकतंत्र ने नेपाल में जबरदस्त अंगड़ाई ली। कुछ दिनों तक यह शांतिपूर्ण दौर जारी रहा किंतु फौज में माओवादी गुरिल्लों को समाहित करने के प्रश्न पर हुकूमत के अंदर लावा फूट पड़ा। माओवादी मिली जुली सरकार से अलग हो गए। माओवादियों का एक हिंसक इतिहास रहा है, इसीलिए सदैव ही ख़ौफ बना रहता है कि राइफलों को लालसलाम कहकर बहुदलीय लोकतंत्र की मुख्यधारा में शानदार शिरकत करने वाले माओवादी अपनी राइफलों को कहीं फिर से न उठा लें? और नेपाल में बड़े पैमाने पर खून खराबे का आग़ाज़ न हो जाए।

माओवादियों द्वारा संचालित विगत तीन दिनों के नेपाल बंद के दौरान भयावह हिंसक वारदातों ने संपूर्ण नेपाल को हिलाकर रख दिया। माओवादियों के सबसे वरिष्ठ सिद्धांतकार बाबूराम भट्टाराई ने आम लोगों के हकों की खातिर किसी तरह की हिंसा को न्यायोचित क़रार दिया है। यह एक अत्यंत खतरनाक संकेत है क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र तो आपसी भाईचारे, बहस और बातचीत पर आधारित है और सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है।

लोकतंत्र की बहुआयामी संस्कृति में बर्बर हिंसा के लिए कदाचित कोई स्थान नहीं हुआ करता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माओवादी एक बार फिर से हिंसक जल्दबाजी के शिकार हो रहे हैं। माओवादियों की यह उभरती मनःस्थिति नेपाल को गृहयुद्ध में धकेल सकती है। माओवादियों का नेपाल के बेहद गरीब किसानों में जबरदस्त जनाधार विद्यमान रहा है। कालेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य भी माओवादियों का बहुत जोरदार आधारक्षेत्र है। सामंतशाही की समाप्ति ने और बहुदलीय लोकतंत्र ने ऐतिहासिक रूप से माओवादियों को अन्य साम्यवादी दलों के साथ मिलकर नेपाल को एक समाजवादी देश के रूप में परिवर्तित करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। नेपाल में सर्वव्याप्त भय विद्यमान है कि अपनी हिंसक जल्दबाजी में माओवादी कहीं इस अवसर को गंवा न बैठें। फिर कहीं हाथ मलते और बहस करते ही न रह जाएं कि कामरेडो ऐतिहासिक गलती हो गई।

माओवादी पूर्वाग्रहों से सराबोर होकर प्रायः भारत विरोधी रवैया इख्तयार करते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नेपाल भारत के बेहद निकट देश रहा है। भारत के संविधान ने भी देश के लिए लोकतांत्रिक समाजवादी समता का लक्ष्य घोषित किया है। नेपाली माओवादियों के द्वारा मुख्यधारा की राजनीति में शिरकत का इस्तकबाल खुले दिल ओ दिमाग से भारत ने किया। भारत भी स्वयं विगत 42 वर्षों से माओवादी नक्सली हिंसा के गहरे जख़्म झेलता आया है। नेपाल के माओवादियों द्वारा हिंसा परित्याग भारत के लिए एक आस उम्मीद की किरण बनकर रौशन हुई क्योंकि इससे प्रेरित होकर भारत के माओवादी भी देरसबेर मुख्यधारा की राजनीति में वापस आ सकते हैं। भारत कदाचित कोई नहीं चाहेगा कि नेपाल गृहयुद्ध की विभीषिका में पुनः जल उठे। इससे तो भारत का भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि नेपाल का। क्या नेपाली माओवादियों को भारत के बरखिलाफ जारी अपने रवैये पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए ? क्या हिंसा का पूर्णतः परित्याग करके पुनः उसकी ओर प्रवृत होने का संकेत एक न्यायोचित कदम है? और नेपाली जनमानस की भावना के अनुकूल है? माओवादियों ने 14 मई,सन् 2010 की सीमारेखा अपनी ओर से तय कर दी है कि तब तक नेपाल को नया संविधान प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा वे वर्तमान सरकार को डीफेक्टो मानकर एक नई सरकार के गठन का ऐलान कर देंगे। भारतीय मूल के नेपाली मधेशियों के साथ माओवादियों के गहन अंतर्विरोध कायम रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर मधेशी परंपरागत तौर पर भारत समर्थक रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामबरन यादव मधेशी हैं और एक शीर्ष माओवादी नेता को पराजित करके नेपाल के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं। नेपाली फौज के सर्वोच्च कमांडर ने जब माओवादी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के छापामारों को सेना में समाहित करने से इंकार दिया था, तो इसी बात पर सारी बात बिगड़ गई। राष्ट्रपति ने माओवादी सरकार के प्रधानमंत्री प्रचंड की हिदायत पर कमांडर इन चीफ को बर्ख़ास्त करने से इंकार कर दिया एवं सरकार में अन्य साझा दलों द्वारा इस प्रश्न पर माओवादियों का साथ देने से इंकार करने पर ही समस्त सियासी संकट उत्पन्न हुआ। तभी से माओवादियों ने खुलकर भारत विरोधी रवैया अपना लिया है। जबकि हालात की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए भारत नेपाल के आंतरिक मामलात में दख़ल देने से सदैव ही गुरेज़ करता आया है और आगे भी करता रहेगा।

सबसे बेहतर होगा कि नेपाली माओवादी अपने क्रांतिकारी धैर्य का कदाचित परित्याग न करें जिसका कि उन्होंने विगत कुछ वर्षों से शानदार परिचय दिया है। नेपाल में दीर्घकाल के पश्चात शांति स्थापित हो पाई थी और वह किसी भी सूरत में आंतरिक अंतर्विरोधों के कारण कत्लो गारत में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। असीम शौर्य और गहन गुरबत से लबरेज़ हिमालयी नेपाल में समस्त सामंती और पूंजीवादी कुहासे को चीर कर यदि समाजवाद का सूर्य उदय होता तो वह यक़ीनन भारत को भी रौशन करेगा । हमारे अपने देश के माओवादी भी हिंसक मार्ग का परित्याग करके नेपाली माओवादियों से प्रेरित होकर और देश की राजनीति की मुख्यधारा में आकर एक समतावादी समाजवादी भारत के निर्माण में अपना समुचित योगदान कर सकेंगे।

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission